न्यूज़ीलैंड के इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट (आपातकालीन प्रबंधन कानून) को मजबूत बनाना

न्यूज़ीलैंड कई प्रकार के खतरों के प्रति संवेदनशील है, जो आपदाओं का कारण बन सकते हैं, जैसे कि बाढ़, जंगल की आग, महामारी, भूकंप या बुनियादी ढांचे की विफलता। एक देश के रूप में हमें आपदाओं से निपटने की अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए अतीत की आपात स्थितियों से सीख लेने की जरूरत है।

सरकार इस वर्ष के अंत में नया कानून लाने का इरादा रखती है, ताकि आपातकालीन स्थितियों के जोखिम के प्रबंधन के तरीके को सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जा सके। यह कानून नागरिक सुरक्षा आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम 2002 CDEM (सीडीईएम एक्ट) का स्थान लेगा।

इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (NEMA) उन मुद्दों और विकल्पों के बारे में आपके विचार सुनना चाहती है, जिन्हें एक चर्चा दस्तावेज़ में रेखांकित किया गया है। आपकी फीडबैक (प्रतिक्रिया) से NEMA को कानून की विषय-वस्तु के संबंध में सरकार को सलाह देने में मदद मिलेगी।

परामर्श प्रक्रिया

संपूर्ण चर्चा दस्तावेज़ तथा अपनी बात रखने के बारे में अधिक जानकारी आपको NEMA की वेबसाइट पर मिल सकती हैं।

इमरजेंसी मैनेजमेंट बिल परामर्श

सार्वजनिक परामर्श 13 मई 2025 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा।

सिविल डिफेंस एमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट (नागरिक सुरक्षा आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम) क्या करता है?

CDEM Act (सीडीईएम अधिनियम) में निम्न प्रावधान हैं:

- सरकारी एजेंसियां, लोकल गवर्नमेंट (स्थानीय सरकार), आपातकालीन सेवाएं और जीवन के लिए जरूरी उपयोगिताएँ (जैसे कि बिजली नेटवर्क) को आपातकालीन प्रबंधन भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ देना
- असाधारण अधिकार जिनका उपयोग लोगों की रक्षा करने और आपातकाल के समय परिणामों का प्रबंधन करने के लिए किया जा सकता है
- राष्ट्रीय और स्थानीय आपातकालीन प्रबंधन योजना के लिए आवश्यकताएँ
- विनियमों या गैर-विधायी दस्तावेजों के माध्यम से आपातकालीन प्रबंधन के लिए अधिक विस्तृत अपेक्षाएँ और उनके लिए मानक निर्धारित करने की क्षमता।

लेजिसलेटिव (विधान-संबंधी) बदलाव की जरूरत क्यों है?

साईक्लोन गैब्रिएल के बाद की गई जाँच और अन्य समीक्षाओं से पता चला है कि CDEM अधिनियम और स्थानीय (जमीनी) स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन के दृष्टिकोण में सुधार की आवश्यकता है।

सरकार का इरादा नए कानून के साथ-साथ गैर-विधायी सुधार (जैसे कि प्रशिक्षण) लाकर पूछताछ और समीक्षाओं का जवाब देने का है। इस काम के लिए सरकार द्वारा फोकस किए गए क्षेत्रों (मुद्दों) पर अधिक जानकारी NEMA की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

आपदा के दौरान लचीलेपन और आपातकालीन प्रबंधन को मजबूत करना

नये कानून के लिए सरकार के प्रस्तावित उद्देश्य तथा उनसे संबंधित मुद्दे नीचे संक्षेप में दिए गए हैं। हमने उद्देश्य 1 के अंतर्गत मुद्दों के समाधान के लिए विकल्पों का सारांश भी उपलब्ध कराया है, क्योंकि हमारा मानना है कि वे समुदायों के लिए विशेष रूप से रुचिकर होंगे।

उद्देश्य 1: समुदाय और ईवी माओरी की भागीदारी को मजबूत करना

इमरजेंसी मैनेजमेंट (आपातकालीन प्रबंधन) में हर व्यक्ति की भूमिका होती है - आपदा से पहले, उसके दौरान और उसके बाद।

सरकार आपातकालीन प्रबंधन के लिए 'सम्पूर्ण समाज' दृष्टिकोण को हासिल करना चाहती है, जहाँ समुदाय 'ऑफिशियल यानि आधिकारिक' आपातकालीन प्रणाली के साथ मिलकर काम कर सकें।

इसका अर्थ है एक आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली का होना, जो समुदायों की विविध जरूरतों की अच्छी समझ रखती हो, विशेष रूप से उन समुदायों की, जिन्हें अधिक बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो आपातकाल से पहले, उसके दौरान और बाद में ईवी माओरी, सामुदायिक समूहों, व्यवसायों, स्वयंसेवकों और अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की गई विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठा सके।

इस उद्देश्य के अंतर्गत हम जिन मुद्दों और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं वे निम्न हैं:

1. लोगों और समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना

इन विकल्पों में निम्न शामिल हैं:

- 1) विभिन्न समूहों को उनकी विशेष जरूरतों या रुचियों के आधार पर आपातकालीन प्रबंधन पर अधिक अनुकूल जानकारी प्रदान करना
- 2) स्थानीय सरकार की आपातकालीन योजनाओं में उन लोगों की जरूरतों पर विचार करने पर जोर देना जिनके आपात स्थितियों से असमान रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है
- 3) राष्ट्रीय योजना को सूचित करने के लिए NEMA के निदेशक को असमान रूप से प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है

2. आपातकालीन प्रबंधन में ईवी माओरी भागीदारी को मजबूत और सक्षम बनाना

इन विकल्पों में निम्न शामिल हैं:

- 1) योजनाओं, मार्गदर्शन और अन्य नीतिगत सेटिंग्स (स्थितियों) में ईवी माओरी की भूमिकाओं को संबोधित करना
- 2) स्थानीय सरकार आपातकालीन प्रबंधन निर्णय लेने वाले निकायों में ईवी माओरी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है
- 3) आपातकालीन प्रबंधन योजनाओं के विकास के दौरान स्थानीय सरकार के लिए ईवी माओरी के साथ जुड़ना जरूरी है
- 4) राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए NEMA के निदेशक को माओरी हितों और ज्ञान पर सलाह लेने की आवश्यकता है

3. आपातकालीन प्रबंधन में समुदाय भागीदारी को मजबूत और सक्षम बनाना

इन विकल्पों में निम्न शामिल हैं:

- 1) सामुदायिक समूहों के लिए बेहतर जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना
- 2) स्थानीय सरकार की आपातकालीन योजनाओं में यह बताना अनिवार्य है कि वे जनता से प्राप्त सहायता प्रस्तावों का प्रबंधन किस तरह से करेंगे

4. यह स्वीकार करना कि लोग, व्यवसाय और समुदाय अक्सर किसी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति/ समूह होते हैं

इन विकल्पों में निम्न शामिल हैं:

- 1) आपातकाल के दौरान सद्भावना से काम करने वाले लोगों को अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान करना
- 2) कुछ परिस्थितियों में, जब लोगों को आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों द्वारा काम सौंपा जाता है, तो उसमें लगी मेहनत के लिए मुआवजे को सक्षम करना

उद्देश्य 2: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर स्पष्ट उत्तरदायित्व और जवाबदेही प्रदान करना

आपातकालीन प्रबंधन में अनेक संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। ये भूमिकाएं और जिम्मेदारियां CDEM Act (सीडीईएम अधिनियम) और अन्य विधायी दस्तावेजों में निर्धारित की गई हैं।

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सबके लिए यह स्पष्ट हो कि कौन क्या करेगा, संगठन एक साथ कैसे काम करेंगे, तथा CDEM अधिनियम के तहत कानूनी जिम्मेदारियां रखने वालों के लिए जवाबदेही की स्पष्ट सीमाएं हों।

इस उद्देश्य के अंतर्गत हम जिन मुद्दों और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं वे निम्न हैं:

5. किसी आपातस्थिति के लिए समग्र परिचालन प्रतिक्रिया का स्पष्ट निर्देशन और नियंत्रण, जिसमें यह तब भी शामिल है जब कोई 'आपातकाल की स्थिति' घोषित नहीं की गई हो
6. आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्रीय नेतृत्व और समन्वय को मजबूत करना - भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, जवाबदेही को स्पष्ट करके और कार्य-प्रदर्शन को मजबूत करके
7. यह सुनिश्चित करना कि आपातकालीन प्रबंधन योजनाओं को अप टू डेट (अद्यतन) रखा जा सके

उद्देश्य 3: आपातकालीन प्रबंधन के न्यूनतम मानक के ऊँचे स्तर को सक्षम बनाना

कई खतरों का प्रबंधन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है, तथा आपातकालीन प्रबंधन विकल्प स्थानीय ज्ञान और उनके विशिष्ट संदर्भ के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

हालांकि यह दृष्टिकोण एक ताकत है, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पूरे न्यूजीलैंड के लोगों के लिए स्वीकार्य परिणाम हों।

इस उद्देश्य के अंतर्गत हम जिन मुद्दों और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं वे निम्न हैं:

8. यदि कोई व्यक्ति या संगठन अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो राष्ट्रीय अपेक्षाओं को निर्धारित करने और प्रदर्शन के मुद्दों की निगरानी और समाधान करने की क्षमता को मजबूत करना
9. स्थानीय सरकार के स्तर पर जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना
10. आपातकाल के दौरान और उसके बाद ताओंगा माओरी (माओरी धरोहर), अन्य सांस्कृतिक विरासत और जानवरों (पालतू जानवरों, काम करने वाले जानवरों, पशुधन और वन्यजीवों सहित) के बारे में विचार को मजबूत करना

उद्देश्य 4: आवश्यक सेवाओं में आने वाली बाधाओं को न्यूनतम करना

हमारा कल्याण (भलाई) उन आवश्यक सेवाओं पर निर्भर करता है जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, हमें सुरक्षित रखती हैं, और हमें अपना सामान्य जीवन जीने देती हैं। हमें अक्सर यह अहसास नहीं होता कि हम इन सेवाओं, जैसे बिजली, संचार या न्याय प्रणाली पर कितना निर्भर हैं, जब तक कि कुछ गलत नहीं हो जाता।

सरकार इन सेवाओं पर आपातकालीन स्थितियों के प्रभाव को न्यूनतम करना चाहती है, ताकि समुदायों को सामान्य रूप से अपना काम करना जारी रखने या यथाशीघ्र सामान्य स्थिति में लौटने में मदद मिल सके।

इस उद्देश्य के अंतर्गत हम जिन मुद्दों और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं वे निम्न हैं:

11. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले बुनियादी ढांचे में व्यवधान (बाधाओं) को कम करना, जिसमें व्यापक बुनियादी ढांचे की पहचान करना, नियोजन को मजबूत करना, तथा सहयोग और सूचना साझा करने में बाधाओं को कम करना शामिल है।
12. यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी संगठन इस बात पर विचार करें कि आपातकालीन स्थिति में इन सेवाओं में बाधाओं को कैसे न्यूनतम किया जाए

उद्देश्य 5: आपातकालीन स्थिति होने पर उचित अधिकार प्राप्त होना

घोषित आपातकाल की स्थिति के दौरान, या रिकवरी (पुनर्प्राप्ति) के प्रारंभिक चरणों के दौरान, CDEM अधिनियम, जीवन या संपत्ति के लिए जोखिम से निपटने या आपातकाल की गंभीरता को सीमित करने में सहायता के लिए असाधारण अधिकार प्रदान करता है।

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन आपातकालीन शक्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया, तथा उनका उपयोग कौन कर सकता है, वे किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हों।

इस उद्देश्य के अंतर्गत हम जिन मुद्दों और विकल्पों पर विचार कर रहे हैं वे निम्न हैं:

13. बंद सड़कों और अन्य प्रतिबंधित इलाकों तक पहुंच का सुरक्षित रूप से प्रबंध करना

14. यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय स्तर पर सही लोग आपातकालीन अधिकारों का उपयोग कर सकें

15. यह सुनिश्चित करना कि आपातकालीन स्थिति के लिए घोषणाएं कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हो सकें, जैसे कि घोषणाओं पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करना

16. यह स्पष्ट करना कि स्थानीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है

अपने विचार व्यक्त करें (अपनी बात कहें)

चर्चा दस्तावेज़ में रेखांकित मुद्दे और विकल्प केवल प्रारंभिक हैं। नये कानून की सामग्री (विषय-वस्तु) पर अपनी सलाह देने के लिए हम निम्नलिखित पर आपके विचार जानना चाहेंगे:

- हमने इस मुद्दे की व्याख्या कैसे की है
- विकल्पों के संभावित लाभ या खतरे (इसमें यह बताना भी शामिल है कि क्या इनमें से कोई विकल्प आपको पसंद है और क्यों)
- कोई नए विचार या वैकल्पिक विचार।

अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर दी गई सबमिशन टेम्पलेट का उपयोग करें या

EmergencyManagementBill@nema.govt.nz पर ईमेल करें

इमरजेंसी मैनेजमेंट बिल परामर्श

सबमिशनॉ (प्रस्तुतियों) का अंग्रेजी या ते रेओ माओरी भाषाओं में होना जरूरी है। आपकी प्रतिक्रिया अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ साझा की जा सकती है, हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जा सकती है, या आधिकारिक सूचना अधिनियम अनुरोध के उत्तर में साझा की जा सकती है। यदि आप ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जिसे आप साझा नहीं करना चाहते हैं (जैसे कि आपका नाम), तो कृपया इसे अपने सबमिशन के साथ भेजी जाने वाली ईमेल में स्पष्ट रूप से बताएं, उन हिस्सों को स्पष्ट करें जिन्हें आप रोकना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए अपने कारणों स्पष्ट करें।

यह जानने के लिए कि आप और आपका समुदाय किसी आपातकालीन स्थिति की हालत में तैयार रहने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां जाएं: <https://getready.govt.nz/>